

## ‘सिमी पर 2019 में लगा प्रतिबंध पूर्णतया जायज’

—जाल खंभाता—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 18 जनवरी। गृह मंत्रालय ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इण्डिया (सिमी) पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो विषय बताए हैं, उनमें है कि सिमी भारतीय राष्ट्रवाद के स्थान पर खलीफाई व्यवस्था निर्मित करने के लिए मुस्लिमों का समर्थन जुटा रहा है। वह इस्लाम की एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था लाना चाहता है और मूर्ति पूजा

■ केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सिमी पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई में कहा कि, जिहाद के लिए युवाओं को एकजुट कर रहा है तथा यह संगठन विभिन्न कट्टरपंथी आतंकी संगठनों से प्रभावित है।

जो “पाप” समझता है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गैर कानूनी गतिविधियों (निरोधक) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत जुलाई 2019 के एक आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर एक याचिका की सुनवाई को स्थगित कर दिया। गृह मंत्रालय ने एक शपथ-पत्र में कहा कि सिमी का उद्देश्य संविधान के मूल ताने-बाने के विरुद्ध है। (शेष पृष्ठ 5 पर)

# ‘पेपर तिजोरी में बंद होता है, तिजोरी से पेपर बच्चों तक कैसे पहुंचा, यह तो जादूगरी हो गई’

## पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को क्लीन चिट देने के बयान पर सचिन पायलट का करारा हमला

जयपुर, 18 जनवरी (का.प्र.)। सचिन पायलट की सियासी दौरे ने राजस्थान की राजनीति में गर्मी पैदा कर दी है। लगातार तीसरे दिन सचिन पायलट ने पेपर लीक मामले को उठाया और इस बार मुख्यमंत्री की ओर से कही गई बातों का मंच से नासिर्फ सीधा

चौधरी, बुजेंद्र ओला और राजेंद्र गुद्धा सहित आठ विधायक थे जिनमें गिर्राज सिंह मलिंगा, वीरेंद्र सिंह चौधरी, इंद्राज गुर्जर, वेदप्रकाश सोलंकी, सुरेश मोदी, खिलाड़ी लाल बैरवा और मुकेश भाकर शामिल रहे। पायलट ने पेपरलीक मामले में अफसरों को क्लीन चिट देने के

- पायलट ने यह कहकर अधिकारियों पर कार्यवाही का दबाव बनाया कि, ऐसा संभव नहीं है कि कोई अफसर जिम्मेदार नहीं है, कोई न कोई तो जिम्मेदार होगा।
- उन्होंने कहा, अधिकारी 5 बजे रिटायर होता है, रात को 12 बजे नियुक्ति मिल जाती है, यह मौका कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए। यह कहकर पायलट ने 20 से ज्यादा अधिकारियों की राजनीतिक नियुक्तियों पर सवाल खड़े किए।

जवाब दिया, बल्कि अधिकारियों को क्लीन चिट देने के अशोक गहलोत की बात पर भी सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं सचिन पायलट ने अधिकारियों को राजनीतिक नियुक्तियों में ज्यादा तवज्जो देने पर भी सवाल उठाए। सुंशुनू जिले के उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के युद्ध में आयोजित किसान सम्मेलन में बुधवार को भारी भीड़ उमड़ी। मंच पर मंत्री हेमाराज

मुख्यमंत्री गहलोत के बयान पर कहा कि जब बार-बार पेपर लीक होते हैं तो हमें दुख होता है। इसके लिए जिम्मेदारी तय करके एक्शन लेना होगा। अब कहा जा रहा है कि कोई अफसर जिम्मेदार नहीं है। पेपर तिजोरी में बंद होता है, तिजोरी में बंद पेपर बाहर बच्चों तक कैसे पहुंचा गया। यह तो जादूगरी हो गई। ऐसा संभव नहीं है कि कोई अफसर (शेष पृष्ठ 5 पर)



सचिन पायलट लगातार तीन दिनों से राजस्थान के सियासी दौरे पर हैं, अपने संबोधनों में पायलट जिस बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, उससे इस शीतलहर के बीच प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त गर्मी पैदा हो गई है। पायलट ने बुधवार को उदयपुरवाटी (सुंशुनू) के मंच से जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने 11 से ज्यादा मंत्रियों एवं विधायकों की मौजूदगी में पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर सवाल खड़े किये। पायलट ने राजनीतिक नियुक्तियों में अधिकारियों को बहुत ज्यादा तवज्जो दिये जाने का भी मुद्दा उठाया। उदयपुरवाटी और शेखावाटी क्षेत्र इन दिनों भारी शीतलहर की चपेट में हैं, इसके बावजूद पायलट को सुनने के लिए नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों की भारी भीड़ जुटी।

## गहलोत की पठानकोट यात्रा

—रेणु मित्तल—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 18 जनवरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पठानकोट जायेंगे, जहां अन्य राज्यों की भांति एक सार्वजनिक रैली आयोजित की जा रही है। गहलोत के राहुल गांधी की रैली में भाग लेने की उम्मीद है। राहुल की रैलियों में अब तक का चलन यही रहा है कि जिस राज्य में उनकी रैली होती है और वहां यदि कांग्रेस की सरकार है, तो वहां का मुख्यमंत्री रैली में मौजूद होता है।

■ क्या गहलोत के विचलित मन को शांति मिलेगी राहुल से बातचीत करके।

सूत्र बताते हैं कि गहलोत का कोई विशेष एजेंडा नहीं है लेकिन वह स्वयं द्वारा 8 फरवरी को प्रस्तुत किए जाने वाले राज्य बजट को लेकर राहुल से चर्चा कर सकते हैं।

गहलोत राहुल गांधी से ऐसे सुझाव मांग सकते हैं, जिन्हें बजट में शामिल करने की जरूरत हो। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री बजट के बारे में जो आ रही मॉडिंस के बारे में राहुल गांधी को ब्रीफ करेंगे। और इस पर भी चर्चा कर सकते हैं कि बजट की मुख्य विषय वस्तु क्या होनी चाहिए।

इन दिनों सचिन पायलट जनसंपर्क अभियान में लगे हैं, जहां उनकी मॉडिंस (शेष पृष्ठ 5 पर)

## ‘राहुल का अच्छा समय’

—जाल खंभाता—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 18 जनवरी। ज्योतिषी तथा पत्रकार से कांग्रेस नेता बने पंकज शर्मा ने बुधवार को कहा कि ज्योतिषीय गणना के हिसाब से राहुल गांधी और

■ पत्रकारिता से राजनीति में आए कांग्रेस नेता और जाने माने ज्योतिषी पंकज शर्मा ने कहा कि, शनि के कुंभ राशि में प्रवेश के साथ आगामी द्वादश साल राहुल व कांग्रेस के लिए करिश्माई साबित होंगे।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि शनि, कुंभ राशि में आ चुका है जिससे राहुल का समय अच्छा हुआ है और आगले 30 महीनों के लिए कांग्रेस की जादुई संभावनाएं हैं।

## कड़कती ठंड में रूस-यूक्रेन में युद्ध नया मोड़ आयेगा?

एक तरफ तो रूस, हर तरह से तैयारी कर रहा है, यूक्रेन के खिलाफ नया और बड़ा आक्रमण करने के लिये दूसरी ओर यूक्रेन मित्र देशों, इंग्लैंड, अमेरिका, पोलैंड, फ्रांस व जर्मनी, से आधुनिक हथियार प्राप्त करने जा रहा है। इंग्लैंड ने अपने आधुनिकतम, ‘चैलेंजर-2’ टैंक सप्लाई करने की तैयारी कर ली है। पोलैंड ने भी नवीनतम टैंक यूक्रेन को देना शुरू दिया है

—अंजन राय—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 18 जनवरी। इस जमा देने वाली जबरदस्त सर्दी में यूक्रेन युद्ध एक नया मोड़ ले रहा है। चूंकि रूस एक नया और बड़ा हमला करने के लिए हर संभव सैन्य कार्यवाही कर रहा है, इस पर यूक्रेन ने भी जवाबी हमला करने के लिए निर्णायक एवं घातक साज सामान प्राप्त करने का पूरा विचार बना लिया है ताकि वह रूसी सेनाओं को उस जगह से खदेड़ सके, जहां इस समय उनका कब्जा है।

सैन्य पर्यवेक्षकों को डर है कि आने वाले दिनों में, दोनों प्रतिद्वंद्वी सेनाओं के बीच और ज्यादा बड़ा खूनू संघर्ष होगा। जहां रूस अपनी सेनाओं

- अमेरिका ने अभी अपने सबसे जबरदस्त “एब्रम्स” टैंक देने का मन नहीं बनाया है, इसके बजाय, अपने बेजोड़ “टैंकिलर” “अर्मर्ड वीहिकल्स” देने का प्रस्ताव रखा है यूक्रेन के समक्ष।
- जर्मनी व फ्रांस ने अपना “मिलिटरी हार्डवेयर”, जो केवल नाटो की सेना को ही दिया जाता था, अब यूक्रेन को देने लिए स्वीकृति दे दी है।
- अब तक, यूरोपीय देश काफी हिचकिचा रहे थे, आधुनिक हथियार यूक्रेन को देने के लिए, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी दी थी कि, किस भी यूरोपीय देश ने ऐसा किया तो उसकी खैर नहीं।

को जमीन पर आगे बढ़ा रहा है, वहीं यूक्रेन रूसी सैनिकों को, खाइयों में लिये गये उनके मोर्चे से खदेड़ने की (शेष पृष्ठ 5 पर)

## पंजाब के वरिष्ठ नेता मनप्रीत बादल ने कांग्रेस छोड़ी

—जाल खंभाता—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 18 जनवरी। पंजाब के पूर्व मंत्री मनप्रीत एस. बादल ने बुधवार को कांग्रेस की प्रार्थमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा देने का कारण कांग्रेस की गुटबाजी को बताया है।

बादल ने राहुल गांधी को दिए अपने त्याग पत्र में कहा है कि “खेद की बात

■ उन्होंने राहुल गांधी को भेजे एक शिकायती पत्र में पार्टी से मोहभंग होने और पार्टी छोड़ने की घोषणा की।

है कि पार्टी में वर्तमान मौजूद संस्कृति और इसमें बने रहने की अनिच्छा के कारण मैं अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा नहीं बने रहना चाहता।” उन्होंने कहा कि “अपने प्रयासों की प्रशंसा पाने के बजाए मुझे अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के लिए पंजाब कांग्रेस में तिरस्कृत किया गया और इस विफलता को वित्तीय लापरवाही ही कहा जा (शेष पृष्ठ 5 पर)

## नॉर्थ ईस्ट के तीन राज्यों के चुनाव नतीजों का बेसब्री से इंतजार रहेगा

दो मार्च को घोषित होने वाले रिजल्ट, साल के अंत में होने वाले राज्यों का “मूड” तय करेंगे

—डॉ. सतीश मिश्रा—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 18 जनवरी। चुनाव आयोग ने देश के तीन उत्तर-पूर्वी राज्यों त्रिपुरा, नागालैण्ड और मेघालय के विधानसभा चुनाव तिथियों की आज घोषणा कर दी। इनके चुनाव परिणाम 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे जिनसे इस वर्ष बाद में होने वाले छह अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए माहौल बन जाएगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि त्रिपुरा में नई सरकार के लिए 16 फरवरी को और मेघालय तथा नागालैण्ड के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। चुनावों के परिणाम 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। नागालैण्ड विधानसभा का कार्यकाल 12 मार्च को, मेघालय का 15 मार्च को और त्रिपुरा विधानसभा का कार्यकाल 22 (शेष पृष्ठ 5 पर)

■ मेघालय का चुनाव ममता बनर्जी के लिए बहुत महत्व रखता है। दो साल पहले उनकी पार्टी ने मेघालय में प्रवेश किया, तथा 17 कांग्रेस विधायकों में से बारह को तोड़कर, अपनी पार्टी में शामिल किया पाला बदलने वालों में मु.मंत्री मुकुल संगमा भी शामिल थे। बारह में से तीन विधायकों ने वर्तमान मु.मंत्री संगमा का साथ छोड़ दिया है।

■ विधायक, मेघालय में कई बार अपनी वफादारी बदलते रहे हैं, इस सबका तृणमूल पर क्या फर्क पड़ेगा, यह इंतजार है सबको।

■ त्रिपुरा में पच्चीस साल से सदा जीतती आई सरकार को अपदस्थ करके भाजपा ने सरकार बनाई थी। पर भाजपा को चयनित मु.मंत्री बल्लुगु पड़ा था। इस बार कांग्रेस व मार्क्सवादी पार्टी गठबंधन बनाकर त्रिपुरा में चुनाव लड़ रहे हैं। अगर त्रिपुरा में यह परीक्षण सफल रहा तो, बंगाल में दोहराये जाने की संभावना बनेगी।

# ‘हिन्दुस्तान के साथ लड़े तीन युद्धों के बाद हमने “सबक” सीखा है’

पाकिस्तान के प्र.मंत्री शहबाज़ शरीफ ने अल-अरेबिया न्यूज़ चैनल को दिये इंटरव्यू में यह भी कहा कि, हम शांति के लिये तैयार हैं

—सुकुमार शाह—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 18 जनवरी। राजनैतिक, आर्थिक, विदेशनीति तथा शासन व्यवस्था के मोर्चों पर अनेकानेक चुनौतियों का सामना कर रहा तथा विवेकहीन नीतियों से हताश पाकिस्तान अब अपने धुर प्रतिद्वंद्वी भारत की तरफ संघर्ष एवं शांति का हाथ बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि उनके देश ने भारत के साथ तीन युद्ध लड़ने के बाद “कई सबक सीख लिये” हैं। शहबाज़ इस समय जबरदस्त दबाव में हैं, घोर आर्थिक संकट के चलते दबाव बढ़ता ही जा रहा है। सुविदित है कि पाकिस्तान इस समय घोर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वे भारत के साथ शांति वार्ता करने के इच्छुक हैं। अभी हाल ही की अपनी यू.ए.ई.

की यात्रा के दौरान, शहबाज़ ने यू.ए.ई. के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायेद अल-नाहयान से कहा कि वे भारत से उनकी बात कराने में उनकी मदद करें। उन्होंने कहा कि अगर भारत के साथ बातचीत करने का कोई रास्ता खुल जाता है तो वे इस देश के साथ निष्कपट बातचीत करना चाहते हैं। “अल-अरेबिया” समाचार चैनल के साथ हुई बातचीत के अन्तर्गत, शहबाज़ ने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने भारत के साथ बातचीत करने के लिये अल-नाहयान की मदद मांगी है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को “सबक मिल गया” है तथा वह शांति के लिये तैयार” है। उन्होंने आगे कहा, “मैंने मोहम्मद बिन ज़सेद से निवेदन किया है कि वे पाकिस्तान के भाई हैं तथा यू.ए.ई. (हमारा) भाई है। उनके भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं तथा वे दोनों देशों

- पाकिस्तान के प्र.मंत्री शरीफ ने यू.ए.ई. के प्र.मंत्री से यह भी कहा कि, वे पाकिस्तान-भारत बातचीत आयोजित करने में मदद करें, और वे (प्र.मंत्री शरीफ) अपनी जुबान देते हैं कि, वे भारत से पूर्ण “ईमानदारी” से बात करेंगे।
- इंटरव्यू के बाद, प्र.मंत्री के प्रवक्ता ने ट्वीट करके यह जोड़ा कि, बातचीत तभी संभव हो पायेगी, जब हिन्दुस्तान 5 अगस्त 2019 को कि गयी गैर कानूनी कार्यवाई को वापस लेगा, तथा कश्मीर विवाद का समाधान यू.ए.ई. द्वारा पारित प्रस्तावों व जम्मू-कश्मीर की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा।
- पर, मजे की बात यह है कि, प्र.मंत्री शरीफ ने पुरजोर ढंग से कश्मीर समस्या की अहमियत पर भारी जोर दिया, पर यू.ए.ई. की यात्रा के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में भी एक भी शब्द कश्मीर विवाद के बारे में नहीं है।

को वार्ता की मेज पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और मैं उन्हें वचन देता हूँ कि हम भारतीयों के साथ पूरी निष्कपटता के साथ उद्देश्यपूर्ण बात करेंगे।” पाकिस्तान के “द डॉन” की एक रिपोर्ट कहती है कि शहबाज़ ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे बातचीत ऐसे वातावरण में हो सकती हैं जिसमें कश्मीर-विवाद जैसी “वास्तविक समस्याओं” पर विचार और उनका समाधान हो सकता है। विवादास्पद प्रश्न यह है कि भारत इस चुनावी वर्ष में पाकिस्तान के इस प्रलोभन को स्वीकार करेगा अथवा नहीं। भारत-पाकिस्तान के सम्बंधों को पुनर्निर्भाषित करने के मामले में कश्मीर भारत का मानना है कि पाक-अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है।

भारत के साथ हुये तीन युद्धों, जिनके परिणामस्वरूप आपसी सम्बंधों में विषाक्तता आई तथा लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ी, की याद करते हुये, शरीफ ने कहा, “हमने सबक सीख लिया है” तथा अब हम शांति से रहना चाहते हैं। शरीफ ने कहा, “भारतीय नेतृत्व तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिये मेरा यह संदेश है कि हम टेबल पर बैठें तथा

कश्मीर जैसे अपने ज्वलंत मुद्दों का समाधान करने के लिये गंभीरता तथा निष्कपट रूप से बात करें।” रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कश्मीर में जारी “मानवाधिकारों के घोर उल्लंघनों” तथा कश्मीर की स्वायत्तता को 2019 में रद्द कर दिये जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने भारत में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का भी उल्लेख किया। शहबाज़ ने इस बात को रेखांकित करते हुये, कि

पाकिस्तान शांति के लिये “बहुत अधिक इच्छुक है” कहा, “विश्व को यह संदेश देने के लिये कि वह वार्ता के लिये तैयार है, भारत को यह सब बंद कर देना चाहिये।” बाद में, प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने एक ट्वीट के माध्यम से यह दिलाया कि शहबाज़ का यह सुसंगत मान्यता रही है कि बातचीत तब तक संभव नहीं होगी, जब तक भारत “5 अगस्त 2019 की गैरकानूनी कार्यवाही” को उलट नहीं देता, तथा कश्मीर-विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों तथा जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप ही होना चाहिये। दिलचस्प बात यह है कि यू.ए.ई. की मदद से संभावित भारत के साथ किसी भी संवाद में कश्मीर विवाद पर केन्द्रित होने पर प्रधानमंत्री द्वारा जोर दिये जाने के बावजूद, यू.ए.ई. -पाकिस्तान द्वारा दो दिन की सरकारी यात्रा के अंत में जारी किये गये संयुक्त वक्तव्य में “कश्मीर” शब्द साफ तौर पर गायब था। यू.ए.ई., भारत के साथ अपने -अपने प्रगाढ़ सम्बंधों की लम्बी चौड़ी बातें करता है। अल-नाहयान के विदेश नीति सलाहकार ने दिसम्बर में यू.ए.ई. में आयोजित “इंडिया ग्लोबल फोरम” में बोलते हुये कहा कि दोनों देशों ने “विश्वास के मंडार” तैयार किया। उस अवसर पर भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा था कि वैश्विक व्यवस्था को नया रूप देने में भारत और यू.ए.ई. महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। अबू धाबी अतीत में भारत-पाकिस्तान तनाव को कम करने में अपनी विशिष्ट भूमिका निभा चुका है। बालाकोट संघर्ष के दौरान, स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने में अबू धाबी की मूक भूमिका सर्वविदित है।